फा.सं.जेड-14014/1/2021-जीसी (ई-3010921)
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011, दिनांक: 12.03.2021

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: फरवरी, 2021 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार ।

अधोहस्ताक्षरी को फरवरी, 2021 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोक्त।

अर्जुन राणा
(अर्जुन राणा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,
मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
6. सचिव, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
7. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. सचिव, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. सचिव, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. सचिव, व्यय विभाग, नई दिल्ली।
18. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
19. सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
22. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव।

फरवरी, 2021 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार

ग्रामीण विकास से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने दिनांक 15.02.2021 को आयोजित अपनी बैठक में, भूमि संसाधन विभाग की अनुदान मांगों (2021-22) की जांच के संबंध में, भूमि संसाधन विभाग के सचिव और अन्य प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

व्यापार करने को आसान बनाने के रजिस्ट्रीकरणसंकेतक की रैंकिंग में सुधार करने के लिए फीडबैक और सुझाव प्राप्त करने हेतु, व्यापार करने को आसान बनाने के संपत्ति रजिस्ट्रीकरण संकेतक के हितधारकों, विशेषतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-रजिस्ट्रारों और अधिवक्ताओं के साथ दिनांक 22.02.2021 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं सहित लगभग 70 हितधारकों ने भाग लिया। इसी तरह, संपत्ति रजिस्ट्रीकरण संकेतक के मुंबई हितधारकों के साथ भी दिनांक 25.02.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अलावा, व्यापार करने को आसान बनाने के रजिस्ट्रीकरण संकेतक की रैंकिंग में सुधार करने के लिए दिल्ली की एजेंसियों द्वारा मानदंडों पर की गई प्रगति/किए गए सुधारों की समीक्षा करने के लिए सचिव, भूमि संसाधन विभाग द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

वाटरशेड अभिशासन: वाटरशेड प्रबंधन में वाटरशेड समितियों/स्थानीय सरकार के कार्य निष्पादन को सुदृढ़ करने के बारे में भारत में विश्व बैंक के निदेशक डॉ0 जुनैद अहमद की अध्यक्षता में दिनांक 23.02.2021 को आयोजित उच्च स्तरीय वेबीनार में सचिव ने भूमि संसाधन विभाग के दल का नेतृत्व किया।

स्प्रिंगशेड विकास में प्रख्यात विशेषज्ञों, डॉ0 हिमांशु कुलकर्णी और डॉ0 संदीप टमटे के साथ स्प्रिंगशेड विकास पर दिनांक 03.02.2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के तहत कुल 6382 परियोजनाओं {8214 (स्वीकृत)- 1832 (राज्यों को अंतरित)} में से अब तक 4769 परियोजनाओं को पूरा किया गया है। फरवरी, 2021 में,1000 करोड़ रु. के संशोधित आबंटन में से 118.93 करोड़ रू. की कुल राशि जारी की गई है।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के विभिन्न घटकों की प्रगति की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

i. 5,98,819 ग्रामों में भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा किया गया।
ii. 4,862उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्रीकरण के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा किया गया।
iii. 1,10,05,407 भूकर मानचित्रों/एफ़एमबी/टिप्पनों के डिजिटलीकरण का कार्य पूरा किया गया।
iv. 3,927 उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों के साथ भूमि अभिलेखों के एकीकरण का कार्य पूरा किया गया।
v. 2,185 तहसीलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना का कार्य पूरा किया गया।

*****